विषय : नेपाल–भारत नागरिक से नागरिक संबंधों का महत्व
(Importance of Nepal- India People to People Relations)
तिथि : 23 अगस्त 2017
स्थानः इंडिया इंटरनैशनल सेंटर

Uddhab: As we all know that the Indo-Nepal relations are being referred to as 'special relations', and also called as *roti-beti ka sambandh* in Hindi. The meaning of these terms differs from people to people. For example, the people of Mumbai have their own perception about the relations with Nepal. Similarly people in Chennai and West Bengal have different perspective. People in Delhi have a much more accommodative perspective in Delhi. But people in other parts of India depend on the political leaders and media to form their views on Nepal. Hence, the so called *roti-beti sambandh* has many ups and downs. So we are having this meeting to create uniform dialogues between the two nations. This is a roundtable conference and views of people will be discussed openly, and no presentations will be made. I now request Mr. Vijay Pratap to chair this meeting.

विजय प्रताप : ये राउंड टेबल हमने इसलिए रखी कि जो लोग पब्लिक फोरम में अपनी बात नहीं कह सकते वो नेपाल के बारे में अपनी बात और नेपाल–भारत रिश्तों में जन–जन स्तर पर क्या होना चाहिए उस विषय पर अपनी बात रख सकेंगे और उसमें भी केवल अपनी बात की सीमा के घेरे में नहीं बल्कि इनको क्या महत्वपूर्ण लगता है उसपर अपनी बात रखेंगे।

हम आप सबके और खासकर नेपाल विज्ञ के सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं वो हर बार हमपर कृपा करते हैं। मैं इस विषय पर अपनी प्रारंभिक बात रखूं उससे पहले एक शिष्टाचार की बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे नेपाली दोस्त जो वहां के कुलीनवर्ग हैं तो जब भी हमारा उनसे संवाद होता है तो उनकी हमसे ये शिकायत रहती है कि हिन्दुस्तान की सीनियर लीडरशिप, राजनैतिक नेतृत्व नेपाल में रुचि नहीं लेती और

शायद पड़ोस में भी नहीं लेती। उनका ज्यादा संवाद अमेरिका, चीन के मुद्दों पर ही रहता है तो इसलिए हम जयराम रमेश जी के विशेष रूप से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना वक्त दिया। वहीं पिछली बार जब हमने संविधान पर चर्चा की थी और पहाड़ के डा. प्रकाशशरण महत जो बाद में विदेश मंत्री भी बने थे उनको बुलाया था और मधेश के लीडर अनिल झा जी के अलावा और भी कई लीडर थे। उस चर्चा में रमेश जी भी आए थे। अन्य बड़े नेताओं को बुलाने में जितनी हील–हुज्जत करनी पड़ती है वैसा रमेश जी के साथ नहीं होता। ये नेपाल में विशेष और लगातार रुचि ले रहे हैं और उम्मीद है कि इनकी कलम और इनकी जुबान से जितनी बातें हम कहना चाहते हैं उससे अगर इनका इत्तेफाक होगा तो शायद उसका वजन बढ़ जाएगा। तो मैं विशेष रूप से रमेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उद्धव जी वहां के एक रजिस्टर्ड संगठन 'दक्षिण एशियाई पर्यावरणीय संवाद' के फाउन्डर हैं। लेकिन इस संस्था के दायरे के बाहर भी ये वहां के मीडिया में अंग्रेजी और नेपाली में लगातार लिखते हैं और लोकतंत्र की जमीन पर खड़े होकर लिखते हैं। उसमें चाहे नेपाली कांग्रेस घेरे में आए या एमाले आए या माओवादी आएं या ऐसे समूह आएं जो बिना जानकारी के, बिना ग्राउंड रिएलिटी अपने लाभ के कारण जो भारत विरोधी धारणा बनाने में लगे रहते हैं। तो उसमें इन्होंने कलम चलाया। प्रो–इंडिया पोजीशन उद्धब जी ने कभी भी नहीं ली लेकिन अपना जो पक्ष रखते हैं उसमें बहस जानकारी पूर्ण होती है ऐसा इनके लेखन के बारे में मेरी राय है। लेकिन अभी जब ये बोलेगें और उसके बाद भी भोजन पर जो इंटरेक्शन होगा तो आप स्वतंत्र रूप से अपनी–अपनी राय बनाएंगे।

हम लोगों ने ये जो बैठक की है इसकी पृष्ठभूमि के लिए मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं। जब तक नेपाली कांग्रेस एक मुख्य पार्टी थी उसके बारे में मैं अपने आकलन की बजाय वामदेव गौतम जो माले पार्टी अलग चलाते थे बाद में उसका मर्जर एमाले पार्टी में हो गया और वो भी एमाले में आ गए। जब राजा ने कू करके सब नेताओं को

जेल में रखा तो साढ़े तीन महीने वामदेव गौतम भी जेल में रहे; ये 2005 की बात है। जेल के बाद, जब ये लोग यहां पर 12 बिन्दु समझौता कर रहे थे, तो उस समय ये सब नेता लोग दिल्ली आए हुए थे तो उसमें उन्होंने कहा कि हमसे साढ़े तीन गलतियां हुई हैं। एक बात जो उन्होंने कही कि जो पार्टियां लैनिनिस्ट प्रिंसिपल पर चलती थीं और उस ढंग से हमारी जो सर्वेहारा की तानाशाही वाली, क्रांति की अवधारणा थी वो अब कालब्राह हो गई है और अब सोशल डेमोक्रेटिक प्रिसिंपल पर ही क्रांति होगी, देश बनेगा और आम जनता की भागीदारी से होगा, सिर्फ कहने की बात रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि नेपाली कांग्रेस को हम लोग भारत के एजेंट के रूप में चित्रित करते थे ये गलत बात है। ऐतिहासिक रूप से वो डेमोक्रेसी के लिए बड़ी फोर्स थे, हैं और रहेंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि भारतीय सरकार और भारतीय जनता ने लगातार लोकतंत्र के पक्ष में हम लोगों की मदद की है और ये जोखिम उठाकर भी की है। जोखिम वाली बात उन्होंने संकेत में की। और आधी बात है कि हम लोगों ने चीन की पर्याप्त आलोचना नहीं की जबकि चीन राजशाही के साथ लगातार रहा। ये साढ़े तीन बातें उन्होंने अपने जेल के पुर्नचिंतन के परिणाम के तौर पर की थी। जो लोग लगातार नेपाल को फॉलो करते हैं तो अगर मैं उन्हें ये बात नहीं बताऊंगा तो ये बात अधूरी रहेगी। वो ये है कि उसके बाद की राजनीति में संसद में उप–प्रधानमंत्री के इस तरह के बयान आए जिनको याद न करना ही बेहतर है। भारत के बारे में इतना तथ्य विहीन और गैर जिम्मेदारीपूर्ण बयान था। ये नेपाल की राजनीति की एक विडंबना है।

दूसरी अब इससे उल्टा देखें तो पहले मैंने आपको वामदेव जी का बताया हमारे यहां से आपको मैं संक्षेप में ही कह पाऊंगा लेकिन हमारे लिए बेकग्राउंड के तौर पर ये रिकार्ड करना जरूरी है। आपको याद होगा कि अभिनेता ऋतिक रोशन ने नेपाली कामगारों के बारे में एक बयान दे दिया था जिससे फिर बाद में नेपाल, काठमांडू में जबरदस्त विरोध प्रकट हुआ था। उसके बाद मैंने राजेन्द्र भवन में अनिल मिश्रा जी के

सौजन्य से एक मीटिंग की थी और उसमें नेपाल के तत्कालीन राजदूत भेष बहादुर थापा आए और दिनभर बैठे। नेपाल से विशेष तौर पर माले के लोग, भारत विरोधी माने जाते हैं हरि रोका जो बाद में माओवादी की ओर से एक नोमिनेटिड सांसद भी बने और दमननाथ ढुगांना भारत–नेपाल के रिश्तों पर एक लिखित बयान लेकर आए थे। उस बैठक में गुजराल जी भी तीन–चार घंटे रहे थे और उन्होंने भारत–नेपाल रिश्तों के महत्व पर और दोनों सत्ता प्रतिष्ठानों पर कैसा रिश्ता है उसपर अपनी बात रखी थी। लेकिन उसमें जो मैं आपसे अभी रघुवंश प्रसाद जी का भाषण शेयर करना चाह रहा हूं; ये आरजेडी के बहुत सम्मानित नेता हैं और तमाम यूपीए प्रतिष्ठान में उनको सम्मान से देखा जाता है। उन्होंने जो भाषण दिया उसमें कहा कि 'हम तो एक ही हैं, हमारा रोटी–बेटी का रिश्ता है'। नेपाल तो भारत का हिस्सा ही है। तो जो सांस्कृतिक रूप से भारत और नेपाल की एकता है उसको हमारे जो राजनेता हैं वो नेपाल की सार्वभौमिकता, अलग अस्मिता, अलग राजनैतिक पहचान इन चीजों के बारे में संवेदना से बात नहीं करते और जो हम लोगों की भू–सांस्कृतिक एकता है, ऐतिहासिक एकता है, उसकी सार्वभौमिकता है उसका वो घालमेल कर देते हैं। और जो भी जो कोई छोटा राष्ट्र होगा और चीन और भारत जैसे दो बड़े राष्ट्रों के बीच में होगा उसमें एक स्वाभाविक और जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें अपने आपको परिभाषित करने का राष्ट्र भक्ति एक महत्वपूर्ण भाव है। अपनी निजी परिभाषा भी आप राष्ट्र की परिभाषा के हिसाब से परिभाषित करते हैं। तो वैसे में ऐसी बात बिना संवेदना के कहना ये हमारे यहां बहुत होता है। ये तो जनता के स्तर पर, नेता तो जनता का प्रतिनिधि है, उस स्तर पर एक समस्या मूलक बात है तो इस बात को हमको बार–बार अपने दायरों में फैलाना चाहिए, बात करनी चाहिए। हमारे यहां नेपाली भाषा संविधान की अनुसूचि में शामिल है। हमारे यहां नेपाली मूल के लोग हैं। वो समझदारी हमारे यहां नहीं है। हम दार्जिलिंग के नेपाली को और भारतीय नेपाली नहीं मानते हैं खुद इस दर्द को दार्जिलिंग के नेपाली ने दर्ज किया है। कि 1950

सन्धी में समान नागरिकता की धारा की वजह (एक्वल नैशनल ट्रीटमेंट) से आमतौर से नेपाली हिन्दुस्तानी और नेपाली, नेपाली को एक मानकर भारतीय नेपाली के प्रति सरकार का बराबर का व्यवहार नहीं है। ऐसा एम पी लामा जी ने भी अपने एक लेख में इशारा किया है।

हमारे सत्ता प्रतिष्ठान को जो नार्मल, International ways by big powers हैं जो conventional ways of state craft है, जिसपर चीन चलता है, सीआईए चलता है उन्हीं पर उनको बहुत कॉनफिडेंस है और वो अब जैसे कॉन्फिडेंस के कई ओबजेक्टिव कारण भी हैं क्योंकि जो cultural infinity है हमारी, oneness है उसका इस्तेमाल करके और अनौपचारिक चैनलस को आप बनाएंगे और कल्चरल इस्तेमाल से जो पॉजिटिव बोंड क्रिएट हो सकता है उसको नहीं क्रिएट करेंगे और पॉलिटिक्स प्रूरलिटी का जो हिन्दुस्तान में है तमाम धर्म हैं, तमाम संस्कृतियां हैं और तमाम राजनैतिक विचारधाराएं हैं तो राष्ट्र हित के नाम पर जो भी सत्ता में हैं वो अपनी ब्यूरोक्रेसी और अपनी एजेंसियों के माध्यम से ही पूरा रिश्ता बनाना चाहता है। उसमें ट्रैक रिकार्ड बहुत माओवादी खासकर जब जन युद्ध हो रहा था तो उस समय का ट्रैक रिकार्ड बहुत बुरा नहीं हैं। पूरी दुनिया में ऐसे कम उदाहरण मिलते हैं कि पूरी की पूरी प्यूपिल्स आर्मी वो ओवर ग्राउंड हो जाए। यहां हमारे सत्ता प्रतिष्ठान से संवाद में वो भूमिका निभाई माओवादियों से। और उसमें एजेंसियों की ज्यादा भूमिका थी तो इस माने में वो बात सही है। लेकिन जितने ज्यादातर डिर्टोशनस हैं भारत–नेपाल रिश्ते में जिस तरह से हर नेता हर फेक्शन नेपाल में हमारी इस्टैब्लिशमेंट से रिश्ता बनाना चाहता है और जो उनके लिए यहां के ऐसे राजनैतिक शक्तियां और समूह हैं जो अपने यहां की राजनैतिक मैं घटिया शब्द में बात सीधे संप्रेषित हो जाएगी। अपने यहां की राजनीति और उसके केरियर को छोड़कर जो मुख्यतः नेपाल सोलिडेरिटी के काम करते हैं अगर वो सत्ता में नहीं हैं तो वो उनसे एक सेफ डिसटेंस बनाकर रखते हैं। तो भारतीय इस्टैब्लिशमेंट अपने अनौपचारिक चैनल्स पर ज्यादा निर्भर है, नार्डिक कंट्रीज

की तरह open transparent pluralist frame work में वो नेपाल–भारत की जनता के बीच में रिश्ता बने इसके लिए कोई टैक्स पेयरस की मनी बहुत स्पेयर नहीं करता। अपने–अपने ढंग से हमारे सत्ता प्रतिष्ठान। यहां एक फुट नोट में मेरी जो समझ है वो हो सकता है गलत भी हो। मेरा एम्प्रेशन ये है कि यूपीए इन्वेस्ट नहीं करता था उसको भी अपनी ब्यूरोक्रेसी में वो था और यूपीए में कांग्रेस जो मुख्य पार्टी थी उसको ये लगता था कि हम पावर में हैं तो ब्यूरोक्रेसी हमारा ही काम करेगी तो उसके नेता भी प्रणव मुखर्जी और कुछ चंद नेताओं को छोड़कर कोई नेपाल के मुद्दों पर रुचि नहीं लेते थे। लेकिन हम लोग जो रुचि लेते थे, हम लोग जो काम करते थे उसमें कोई बाधा नहीं बनती थी। उनको सीधे कोई नहीं कहता था कि समाजवादियों से और आरएसएस वालों से आप क्यों मिल रहे हो चीजें तो हम तय करते हैं। लेकिन अब नेपाली मीडिया को बुलाकर, नेपाली राजनैतिक मित्रों को बुलाकर सीधे ये कह दिया जाता है कि 'अब हम तय करते हैं'। और जो हमारी जानकारी हमारी है वो यहां बहुत सीमित 'हम' हो गया है। तो ये अपने आप में दोनों देशों का जो साझा, सांस्कृतिक रिश्ता रहा है वो अतीत की चीज न बन जाए क्योंकि जैसे वेस्ट एशिया में सभी राष्ट्र इस्लाम को मानने वाले हैं और उनकी आपस में कितनी मोहब्बत है उसके बारे में यहां कहने की जरूरत नहीं है। तो केवल हिन्दू होने और हिन्दू राष्ट्र आप संविधान में डलवा भी देंगे; अभी सब्सेन्टिविली डलवा तो दिया गया है लेकिन वो शब्द नहीं है। कनवर्शन का गैर कानूनी है, गाय का वध गैर कानूनी है। सनातन संस्कृति की रक्षा करना संविधान में दायित्व है जनता का तो सब्सेन्टिवली आपने उसको हिन्दू राष्ट्र बना दिया लेकिन वो शब्द डल जाए इसके लिए हमारा सत्ता प्रतिष्ठान खासकर नॉन ब्यूरोक्रेसी का जो पॉलिटिक्ल सत्ता प्रतिष्ठान है वो कई स्तरों पर लगातार इसपर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि वो जो वास्तविकता है, हमारी और उनकी, नेपाल की सांस्कृतिक वास्तविकता है उसको वो प्रदर्शित नहीं करेगा बल्कि उसका वाइलेशन होगा। तो मैं ये जो बैठक है ये एक तरह से नेपाल के

सत्ता प्रतिष्ठान कि यदि आप अपने को 'सार्वभौमिक' देश मानते हैं अपने को तो सार्वभौमिक नेता की तरह अलग–अलग फैशनल बैटल में हमारे इस्टैब्लिशमेंट की ओर देखना उसमें साथ देना और पब्लिक में कहना कि नहीं भारत का ये हस्तक्षेप बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। तो माइक्रो मैनेजमेंट, इंडियन इस्टैब्लिशमेंट का तभी खत्म होगा जब नेपाल का जो अभिजन है, रूलिंग क्लास है, रूलिंग एलीट है वो आपस में खुलकर और ईमानदारी से संवाद करे। एक–दूसरे को जैसे मैंने वामदेव जी की बातें बताईं आपको उस तरह से उसको अंडरमाइन न करें। अपने यहां भी डेमोक्रेसी है और वहां भी डेमोक्रेसी है तो हम एक नकली थोपी हुई राष्ट्रीय सहमति न तो नेपाल में हो सकती है न हिन्दुस्तान में हो सकती है और इस डिबेट को ओनेस्टिली किया जाए। पोपलिस्ट ढंग से इरिस्पोनसिबली न किया जाए क्योंकि पूरी दुनिया में घृणा और संगठित घृणा से राजनैतिक लाभ लेना ये यूएस में तो हुआ ही है यूरोप में भी उस तरह की प्रवृतियां आ रही हैं। बाल–बाल बचे फ्रांस वाले इस तरह की राजनीति के कंट्रोल में आने के। तो ये एक पूरा संदर्भ है जिसमें हम दोनों सत्ता प्रतिष्ठानों से अपनी बात कहना चाहेंगे और आज जिस तरह से जयरामजी और जोगेन शर्मा जो पॉलिटिक्ल क्लास को रिपेरीजेंट करते हैं और तमाम देश के बड़े नेपाल हैंडस यहां हैं वो अपनी बात भी रखेंगे और हमारी बात में जो कमी है वो भी रखेंगे।

Udhhab: It is very difficult to speak in a forum where there are many who are very knowledgeable about Nepal and also many who are not familiar with it. Hence, I will start by talking about the special or *roti-beti ka sambandh*. It is special because there are marital as well as economic relations between the people of these two countries. Also, we could see relationship between two armies; Nepal's army chief is the Honorary Army Chief of India and his counterpart in Nepal is the Honorary Army Chief of Nepal. This is a very unique relation. Also a Nepali citizen can travel to India on a Nepali passport without any visa or permit and stay in India as long as he/she likes. These are the important aspects of our special relationship. Most of the above mentioned indicators of "special" relationship are to be considered as outcome of the

1950 treaty and the open border provisions between two countries. The people to people relationship and open border issues are directly linked to each other. But today, provisions of open border as well as 1950 treaty are being criticized by many stakeholders. People of Gorkhaland Movement, people of Darjeeling, etc. are saying that it has made Indian establishment difficult to differentiate who are Indian citizens and who are Nepalese. They are worried about the similar national treatment that the people speaking Indian and the people with Nepali nationality get. Even in Nepal the 1950 treaty is being questioned along with the open border issue saying that the country could not prosper because of it. But couple of changes have taken place in the recently after 2007. Before the Madhesh Movement, Nepalese were treated as a single entity by the Indians without discrimination whether they were belonged to the hills or Madhesh. But nowadays, Nepalese are asked whether they belong to the hills or Madhesh. Many Indians feel that the people belonging to the hills are tilted towards China and could be anti-India. This is my personal experience during my travel to Jharkhand and Mumbai after the Madhesh Movement. As I mentioned earlier inner parts of India do not have their own perspective of Nepal. Many of them don't even know where Nepal is situated. They think that Nepal is more inclined towards China than India, and is serving as a major threat to India. This makes it clear that their perception is based on the information they get form the government and the media. Or there is no people to people interaction between them. So that is the main reason because of which there is a need to have informed dialogue between the two countries.

We have to examine whether there is any paradigm shift between the Indo Nepal relations historically. As Vijay Pratap pointed out, there were ups and downs in the relations during the UPA rule. Nepal also faced a blockade in 1989 under their rule, but the criticism in those days was that the UPA government outsourced the Nepal policy towards bureaucracy and security apparatus. The reason behind this was, that there was no high level visits from Indian side to Nepal even if their Nepali counterparts used to visit India as regular as today. So hence, this led to such tensions between the relations of the two countries, and this was the main criticism that was happening in those days. But ever since BJP came to power, BJP addressed this concern almost immediately after coming to power. PM Modi and President Pranab Mukherjee have also visited Nepal in the last two years. Even the Joint Commission meeting, the highest level mechanism of both countries at the foreign ministry level was held after a gap of 17 years. Despite all these events, the question remains, that whether the Indo-Nepal relations have

improved or not. As I said earlier, relationship has not been improved between two countries even if the two governments tried to correct the courses. The way there are divided viewpoints about Nepal and Nepalese in India can be taken as example. Also, anti-Indianism was increased at the people's level especially to those belonging to the hills in Nepal and the main reason were the difficulties they faced during the blockades after the earthquake. Even in Madhesh this anti-Indianism is being grown up. The reason behind it is India's withdrawn support to the Madhesh Movement. The perceptions of the Madhesh party is that, they were not originally not going to take part in the local elections but are now compelled to do so now, due to the push they are receiving by India. So this the main cause of the feeling anti-Indianism growing in Madhesh. The post blockade and post earthquake scenario is that the Nepalese are very happy to connect with China via the One Belt One Road in the name of development. Indian friends who travelled to Nepal recently have shared their feeling saying Nepalese started showing coolness while interacting with Indian counterparts. That is why we feel the need for an informed dialogue among the people between India and Nepal.

There are the policies by China that is going to affect South Asia. However, these issues are not properly discussed in Nepal. Nepalese are supporting China as far as possible without reviewing China's attempt critically; and the motto is to counter India. This has become mindset of Nepali people. That is why the issues i.e. 1950 treaty and the open border which according to me have been the safety vault for the poorest of the poor people of both the countries. There is a need to deconstruct some of the believes that mostly the rich Indians are migrated in Kathmandu to do business and only the poor Nepalese are in India to work. The Uttar Pradesh government had to sent over 500 buses to help rescue its people from Nepal during the earthquakes. It states that a huge number of poor Indian as laborers, street vendors etc. are working in Nepal. They are there only due to the open border provisions and 1950 treaty since 1950 treaty is being questioned from various corners two governments should discuss if there are any unequal clauses, and addressed and revised immediately. While doing so the pro-people and pro-poor clauses should be continued. For that people's level informed dialogues and discussions to be continued. Otherwise, future generation will forget the especial or *roti-beti ka sambandh* we are discussing today.

Gen. Ashok Mehta: This is very important conference. In every such conference *roti-beti* has always been discussed. A Nepali journalist recently told me that, we keep revelling about this *roti-beti* and 'special relations', but the actual fact is quite different. You will hear about this *roti-beti* a lot over the next three or four days, without addressing the ground reality. As a soldier, I know Nepal since 1959. I walked from Mechi to Mahakali and from Janakpur to Jomsom yearly. I know the Indian Gorkha soldiers of the Indian army very well. The ex-servicemen community in those areas form a strong pro-Indian constituency. The Indian ambassadors in Nepal are the Gorkha soldiers. There are over a lakh Gorkha soldiers there and are called ex-servicemen. They cross the open borders, pick up their bottles of Hercules rum and go away by saying that there is no country better than India. They get their liquor, their day to day needs, their food, their medical treatment and all their basic needs through India. A couple of years ago, in Kathmandu, a few Nepali people invited me to a restaurant and said to me that the Indian government should keep the perspective of the commoners of Nepal into consideration while deciding upon their upcoming policies. There was a serious debate that went on for hours on this issue. I said to them, that you are absolutely correct, because the government functions for the population of the 29 million people living in Nepal. The government to government relations will only happen between the governments and not the commoners. The relations between the governments of the two countries will depend entirely on them and not anybody else. So the people to people relation is completely ignored. It is not a factor in the politics of India and Nepal. In today's date each people to people relation has 6 -7 million Nepalis. But these are not Nepalis who have settled in India. Today more than 7-8 million Nepalis are working in India. The rest are working abroad. So more than half the population of Nepal is outside Nepal. So on that basis the people to people relations between Indian and the Nepalis should have been very good. But because the Indians have treated the Nepalis is a very bad way in India, it is not very easy for them to forgive us for our misbehavior. When Madhuri Dixit was a budding star, I had gone to Kansas to give a lecture on India Nepal. A person just before my lecture exclaimed, that India is very lucky to have Nepal as a constituent part of it. Madhuri Dixit also said the very same thing. When the former C.M of Delhi, Madan Khurana had gone to Kathmandu, he said Nepalis are great people because they serve as good servants and good watchmen. If one talks about Nepalis in such a manner, do you expect them to take it nicely. When I used to go on my walks to Gorakhpur, Janakpur, Nepalgunj and other places in those

areas, I found the local residents there used to use an abusive term referring to the Nepalis. You treat the Nepalis is such a way and then talk of 'special relations'. How can you talk of 'special relations' after you humiliate the Nepalis domiciling in Indian and the others who keep coming and going. The anti-India sentiment in their hearts was politically motivated, but you too have been responsible for it. In the Kathmandu valley and the Pokhra valley after the blockade in 2015, a parallel economy had to be created, because the blockade completely cut off all the daily and essential supply of the people living in those valleys. The blockade in 1989 did not create any such problems. So the recent blockade created an anti-India sentiment in their hearts and one can't really blame them for it. Some of it is genuine and the rest is contrived and is a great disadvantage for India. K.B Maharaj, the foreign minister of Nepal, Nepal will be neutral on the Doklam issue between India and China. Another Nepali journalist asked me my views on this. I said that he is going by what Prithvi Narayan Shah said that Nepal is a yam between two boulders. That position has never been more real than it is today. So K.B Maharaj is comment on India and China's Dolkam issue completely reflects this. The journalist also asked me about the 50,000 Gorkhas in the Indian army. What will be K.B Maharaj's take, if a war breaks out? Will he support the Nepalis in the Indian army, or will he still take a neutral stand? Soldiers of the 4/8 Gorkha Rifles are deployed in Doklam. They are soldiers who are confronting the road construction party in Doklam. So the situation is such that a war can break out at any point of time. So Nepal is in a very tricky position. My last point is on China. Never in the history of Indo-Nepal relations has the China factor been deeply embedded as it is today. Before the Maoist revolution the Chinese used to call the Maoist hijackers of the fair name of Mao. The Chinese ambassador at that time was sacked, because his assessments proved to be wrong. The Chinese in those days used to say that they do not interfere in the politics of any country. According to my information, this was a completely false statement. The Chinese are involved in every political party in Nepal, including the Madheshis. Political parties have ingratiated themselves to the Chinese in ways that nobody can think about. The highest official in a political party to the lowest official are in the Chinese's pockets. They have deep pockets and they will use their economic wealth to by influence and shape the future politics in Nepal. The former Nepali P.M Prachanda used to always talk about 'special relations' whenever he was in India, but when he went back to Nepal, he completely ignored that term. In 2008, he used to say, that we have to use China, to balance India. After he was out of power, and was made P.M in many ways by

agencies and organizations, who work on behalf of India, he told me that I have realized that for Nepal, India matters more than China. But this statement is illogical. Situation hasn't changed in the last 9 years. The Belt and Road project is already in progress, and K.B Maharaj is busy with that. He has signed the framework agreement with China. So even though China has always been a part of the Indo-Nepal relations, it has transformed and is part of the relations in a completely different shape today. It is there as a rival and a competitor. Every SAARC country has a Chinese presence. Chine is challenging India in every respect. So while talking about 'special relations', *roti-beti* and people to people, one should keep in mind that this one factor can make the difference between India and Nepal relations. The aim of the Indo-Nepal relations is form a government is Kathmandu that is favorable towards India. The Chinese will challenge it always, and that is the biggest challenge that India is facing today. And no amount of any type of people to people relations can alter that fact. People are not going to make any difference about who the government is in Kathmandu. If the government is not favorable towards India, then the task of improving Indo-Nepal relations and *roti-beti* is going to be much tougher. So one has to keep in mind that everyone who comes from Nepal and works for you as a servant, or labor or any other employee, is a very important person. He/she is to be treated with honor. This is the main factor that one needs to think about. Why is there this blatant and reluctant anti-Indian feeling that is there in the Nepalis' hearts. It is the commoners who employee Nepalis are responsible for it.

K. V Rajan: Let me come straight to the point. They are related to the importance of people-to-people relations that we are discussing here.

There are two basic challenges that India and Nepal are facing. On the Indian side there is concern that the legitimate security concerns of India are not receiving the kind of sensitive attention in Nepal that they deserve from a true friendly neighbor. This has become an obsession. The perception in India is now widespread that there is a growing tendency of Nepal getting closer and closer to China, irrespective of India's sensitivities. On the Nepalese side there is a tendency towards a potentially self=destructive variety of ultra-nationalism, which is neither good for India nor for Nepal nor for Indo-Nepal relations. There is also this perception about India that Gen. Mehta just spoke about. That India has its own agenda; India is trying to interfere etc. It is more often than not a question of perception, style, how policies are implemented, rather than of policies as such or intentions on either side.

This is a potentially dangerous and explosive combination of challenges that India and Nepal face, and the only way to tackle them is to recognize the importance of the people to people relationship. If we don't recognize it, if we don't utilize it, if we don't nurture this, and that too with a sense of urgency, then I think even the people to people relationship will be overwhelmed, by these other concerns that I am talking about.

I had personal experience of the usefulness of people to people relations and the way in which they could be affected sue to the inability to proactively manage the Indo-Nepal relations at other levels, in the five and a half years that I spent in Nepal as the Indian Ambassador. The Madhuri Dixit episode happened in 90s when I was there. She had come there for the launch of a certain film and while talking to people, she innocently said that Nepal at one time was a part of India. I was asked by people, to ignore this because nothing was going to happen, as she was after all a celebrity even in Nepal. However, after she reached Mumbai, I had to fax her to immediately, retract this statement I knew that it would hurt the sentiments of the Nepalese deeply, and I was right. By 6 a.m next morning people had lined up in front of her hotel protesting against the statement she had made. So it's a question of understanding sensitivities and taking the necessary steps in time.

The real downturn in people to people relations began when the IC 814 aircraft was hijacked. I happened to be in Nepal at that time. That was one incident that really wrecked the image of Nepal as a country in India. Nepal was a favorite place for parents to send their children for their honeymoon. But then people started saying that they did not want to send anyone to Nepal, because the Indian media blamed Nepal in disproportionate ways for the hijacking, and projected a very wrong image of Nepal in the minds of the Indians. For the Indian Airlines flights to resume between Kathmandu and Delhi, the negotiations were very long and very tortuous. Kathmandu is the only airport in the world where a passenger is not allowed to be frisked just before boarding the aircraft. While negotiating with the Nepalese, we were told that they would not allow Indian security officials to frisk passengers on Nepali soil. Hence the frisking takes place after the passengers climb up a few steps just before entering the aircraft. So this kind of sensitivity is considered as an inability to understand the genuine security concerns by the Nepalese side according o the Indian perspective.

People to people relationship come in handy also at times of political instability when bilateral cooperation has to be sustained despite changes of government. When the Mahakali treaty was about to be ratified, I remember a leader of the Nepalese opposition calling on me and saying, that this treaty is in Nepal's favor and we are definitely going to ratify it, but the government was going to change soon and a new government would soon come to power. So just wait for a few days and we will ratify it. I said India was not going to interfere in Nepal's domestic politics; the Nepalese parliament should do whatever they feel is in the nation's interest. Sher Bahadurji was the P.M, the Treaty came up for ratification and it was ratified. But the opposition leaders were so upset with me, for not following their advice that they started agitations against India, at the people to people level. For example, a chain of human hands was organized to protest something or the other. I thought that the best way to tackle the people to people challenge was use the people to people mechanism myself. I remember there was a team from the National School of Drama (NSD) in Kathmandu at that time, training Nepalese artistes to perform a play in Nepali, and we decided to stage it at the time when the human chain was being formed in Kathmandu and was evoking a fantastic response from the people of Nepal and was threatening to spoil the atmosphere of the Indo-Nepal relations. When this play was staged at the NSD, the human chain just broke up. People refused to join the human chain and were more interested in watching the play. So the point is that, this is the powerful tool i.e. the people to people relationship that both countries have. This should not be underestimated while overriding the vested interest of some people to threaten or undermine ties.

Nepal has two great assets, hydro power and tourism. If they are tackled, Nepal will be the richest SAARC country. Nepal is not able to tackle these two because we are leaving everything to the governments. So the Pancheshwar treaty that was signed and ratified by Parliament during my time is still being talked about… 20 years after the event. This is because we have not exploited the people to people angle. If people on both sides of the border river Mahakali could be educated on the benefits to them of the Mahakali treaty, they would have forced the politicians to expedite the implementation of the treaty. But that didn't happen. So you are dealing in a compartmentalized way, as if everything is done in a vacuum between the two governments in New Delhi and Kathmandu.

And now that Nepal is going to be a federal country and India already is a federal nation, why on earth do we always talk about Delhi-Kathmandu? This *roti-beti* relationship is excellent for banquet speeches. But that is just related to the Hindi speaking belt and the Madheshi people. Why aren't more people In Nepal going to Chennai and Bangalore or other regions for different purposes? Let us now deal with the relationship at the level where it will increasingly count. Sister city relationships, local government relationships, state governments' relationships should play their full part in building a sustainable bilateral relationship.

Security should not be in the driving of the relationships. A reference was made to the perception that India micromanages relations in Nepal. It is true to an extent. I recall that one of Nepal's legendary thinkers Ritikesh Shah wrote a letter to Jawaharlal Nehru, asking for advice. Nehru was willing, but reminded Shah that the problem is that when Indians give advice in response to such requests, Nepal calls it interference. So that is exactly the thing that is happening. There is too much of inclination on the part all Nepalese political leaders, to seek India's advice, as though it really matters.. Actually I think it is overstated, and Indian's advice when it is given doesn't matter all that much.

So it is partly mismanagement of relations at the government level, partly the policies that need to be changed, partly perceptions, the style and vested interests exploiting every opportunity offered to them.

My suggestion on the 1950 treaty is that, it is not at all beyond the ingenuity of the diplomats on both sides to modify the treaty, so that it doesn't become an irritant in the relationship. India as the larger country should take the initiative. Nepal wants the benefits that it gets in India, but also to be respected as a sovereign independent country. Surely, today, India can be big hearted enough to accept in a formal Treaty that Nepal is a sovereign independent country. India should take the initiative of giving Nepal the concession it seeks as a smaller and vulnerable neighbor, as long as its security concerns are respected. Instead, it is repeatedly asking the Nepalese side what they want, and when they request for a few changes to be made in the articles, hint is thrown about the possibility of withdrawing the concessions given to the Nepalese in India. If two countries are genuine friends, then their 'special relationship' should go beyond the 1950 treaty, and should extend to modifying the 1950 treaty. It is important for Nepal to accept India's legitimate security concerns.

Nepal also has to accept that there is no question of comparing India and China. China will never be the kind of sincere friend of Nepal that India is. The sooner that happens, the better it is for the bilateral relationship between the two countries. India is quite comfortable with Nepal and China expanding their friendship and cooperation, but any thought of blackmailing India into giving more concessions by playing a China card is a very dangerous game and could have adverse implications for the relationship as a whole if it influences government policy.

Sr. Adv. Dinesh Tripathi: The relation between India and Nepal was made by the people of the two countries, before the government to government relation. If there is any irritant between India and Nepal, it has to be addressed in a timely manner and there has to be some trust building process. The reason being that, animosity between two countries is unaffordable. There are three factors that are important. Firstly, there should be constant communication, between the two countries, not only at the government level, but also at the people to people level and the civil society level. The track II diplomacy is critically important to strengthen the relation between two nations. This will help in resolving any irritant issue and building trust. Connectivity is also very important, because that will play a major role in building trust between the two countries. Cooperation should also be there. Nepal is a small country, but it has a huge potentiality in terms of water resource and there are so many things that Nepal has to offer. So we need to find out the areas of collaboration rather than areas of differences. How can we collaborate and how can we harness the natural resources in a mutually beneficial manner is also an important factor. Since there is a paradigm shift, the establishments of both the countries have to think out a box in which they will have to include the paradigm shift area of cooperation, area of collaboration and with the help of communication and dialogue we can overcome the trust deficit scenario. Nepal is a sovereign country, so they should accept the legitimate concern of the Indian side and India should also show sensitivity towards the Nepalese concerns. Both the countries are sovereign nation and the member of UN and both nation believe in principle of sovereign equality , even though there is a asymmetry in terms of size and population. So with the help of mutual respect and mutual cooperation, we can have a better relationship between the two countries. The duty to cooperate is also important principle of International Law, so, both the countries have to cooperate. There is no alternative for cooperation and dialogues. Only alternative to dialogue is

more intense and meaningful dialogue. There is no alternative to cooperation. The only alternative to cooperation is more productive cooperation. We also need to apply a confidence building measures (CBM) between the two countries, because it would remove the irritants between the two countries. If those irritants are not addressed in the correct amount of time, they will damage the relationship between the two countries. If one set of applying CBMs fails, we should apply another set of CBM. Both countries are democratic countries. So the establishments of both the countries should listen to their people. If the establishments of the countries go out of their way, the people from both the countries should put pressure on their respective governments so that they can correct themselves and bound to take a correct path. Both the governments should be accountable, to their respective populations and electorates. Nepal is a initiated federal democratic arrangement. So, now it is going through a phase of transition. The Nepali constitution implementation process is very difficult one, there is series of deadlocks. it is not very smooth. India is a mature democracy and how, so Nepal and India should learn from each other's experience. As ambassador Rajan mentioned, due to the federal arrangement of Nepal, the landscape of the country is going to change and areas of cooperation will also change along with that. Originally it was only Kathmandu and Delhi, but now other provincial governments will also be part of the dialogues and became the new stakeholders. They will also find their own means to collaborate with other Indian state also. So in this new arrangements, apart from Kathmandu and Delhi, but capital of the states and other provinces will also matter. They will also have an important role to play in the relation between the two countries. But this is also going to make the negotiation process more complicated, because the states and provinces will also exert more pressure on the central government. If there is an issue of water sharing, then the central government cannot decide without consulting the states and even the provinces will have their own say in the matter. I just want to finish by saying that there is no alternative to cooperation between India and Nepal. We cannot afford animosity between them. Both the countries should take care of each other's legitimate expectations and legitimate concerns. India should also ventilate its legitimate concern in an open manner. There should be frank discussion on the issues. I think that in a dialogue process, everything can be resolved. So trust deficit scenario can also be resolved by the communication between the two countries. A lot of problems also arise because of communication gap. So hence, communication is the key between both the countries. And civil society can play a major role in this process.

रूचि सिंह : मेरा सबको नमस्कार। मेरा नाम रूचि सिंह है वैसे तो मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं लेकिन काठमांडू से हिमालयनी की एक मैगजीन निकलती है, मैं उसके साथ काफी समय से जुड़ी हुई हूं। मैं 1989 से नेपाल और भारत के संबंधों पर लगातार लिखती भी आ रही हूं और मैं काठमांडू आती–जाती भी रहती हूं। मैंने तीनों शासनकाल देखे हैं राजा के समय का भी, उसके बाद वीपी कोइराला के समय का भी शासन काल देखा है और इस समय का भी शासन काल देखा है। तो मेरा मानना है और मेरा कहना है कि मैं हमारे आदरणीय केबी राजन की बातों और अशोक मेहता जी की बातों से भी सहमत हूं। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अब वो समय आ गया है कि हम अलग हटकर सोचें कि नेपाल और भारत के रिशतों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और उस चीज में मधुरता लाई जाए। सिक्योरिटी के आशय से देखें तो हम जितनी सिक्योरिटी की अपेक्षा करते हैं या इंडिया वाले करते हैं वो उन्हें नेपाल से उतनी मिल नहीं पाती। यदि नेपाल की सुरक्षा कड़ी हो और बाकी सारी चीजें हों तो जिस तरह से नकली नोटों की करेंसी आने की बातें आई हैं। कई बार आती है कि लोग आ रहे हैं, पाकिस्तानी लोग आ रहे हैं आखिर क्यों आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनके नकली आई कार्ड बन रहे हैं। हालांकि इन मुद्दों पर लोग आगे बात करेंगे। रही बात पंचेश्वर और महाकाली परियोजना की तो इन परियोजनाओं पर 1995–1996 में बातचीत शुरू हुई थी लेकिन बार–बार ये कहा जा रहा है कि इसका डीपीआर अभी तक तैयार नहीं हुआ है तो डीपीआर समय पर क्यों तैयार नहीं हुआ है? बार–बार नेपाल में सरकार बदलती रही है। हर तीन महीने बाद, छह महीने बाद, नौ–नौ महीने बाद, एक या डेढ़ साल बाद जिस तरह से सरकार गिरती रही है और जिस तरह से भारत के बारे में नकारात्मकता या नेपाल के बारे में भारत के लोगों में नकारात्मकता पनप रही है उस चीज को हम अब कैसे दूर करें। राजन जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि स्टेट लेवल से भी बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि स्टेट टू स्टेट

लेवल में हम कई तरह के काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम पॉलिटिक्ली लेवल पर ही काम करें, हम कृषि स्तर पर भी काम कर सकते हैं। पर्यटन पर काम कर सकते हैं, संस्कृति पर काम कर सकते हैं। कई ऐसे क्षेत्रों में काम करके हम नेपाल और भारत के रिश्तों को एक अच्छे मोड़ की तरफ ले जाएं और ये तथ्य है कि हमारे जितने अचछे रिश्ते भारत–नेपाल के साथ हैं और जितना भारत नेपाल का साथ दे सकता है उतना चीन नहीं दे सकता। आज नेपाल के प्रधानमंत्री देओवा साहब भारत आ रहे हैं लेकिन सोचने की बात है कि उसके पहले चीन के उपप्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। चीन जिस प्रकार लगातार नेपाल में पैसों का निवेश कर रहा है उससे तो यही लगता है कि जिस तरह से श्रीलंका में चीन ने एयरपोर्ट बनाने के लिए जो कर्ज दिया था। श्रीलंका ने कर्ज तो लिया लेकिन उसे चुका नहीं पाया जिसके बदले चीन ने उसकी जमीन 99 साल के लिए लीज पर ले ली। हम लोगों को तो अब ये भी डर लगने लगा है कहीं ऐसा न हो कि चीन, नेपाल में इस हद तक अंदर न घुस जाए कि वो नेपाल को कह दे कि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं और आप अपना सब हमें दे दें। डोकलाम मुद्दे पर आखिर चीन को क्या जरूरत थी नेपाल के पास जाने की, कोई जरूरत नहीं थी। इस चीज को देखते हुए हमें गंभीरता से देखना पड़ेगा कि हम इन हम इन रिश्तों में जो पेंच फंसे हुए हैं उन्हें कैसे सुधारें, कैसे निकालें और हमारा नेपाल–भारत के रिश्ते कैसे अच्छे हों और आगे बढ़ें। धन्यवाद।

Prof. Rekha Sexena: I work on federalism, and that as someone said that Nepal has become a federal democratic country, I would like to say something on that. I have been visiting Nepal since 2005, and almost every year I go there and interact with bureaucrats, politicians, academicians and civil society members. I think despite this track one diplomacy, people to people contact, track to diplomacy is very important. I was recently in China, and I had been invited there by the Chinese on a meeting of the Doklam issue. It was a friendly Indo-China meeting. They were telling us, that India should withdraw their troops from Doklam, but they

were also keen on forgetting all this and moving towards a dynamic relationship between India and China, because they were two Asian giants. They also felt that they will be able to end the hegemony of the west by joining hands. China also realize important of this friendship. I think India and Nepal have been friends for a long time and they value this long lasting relationship very much. I think it is in the future interest of Nepal, that India and China should stay together and maintain a friendly relationship. Border issues are still there, but they can be resolved. I have even interacted with the Maoists in Nepal, and they told me that they do not like open borders and they think that we should have closed borders. They are more interested in having open borders with China. I think that when track one diplomacy fails, track two diplomacy can do wonders. I have also been working on article 370 and I think that we should try to build a cosmopolitan politics in Kashmir. Since Nepal has moved towards a federal constitution, there will be new stakeholders in Nepal, new issues will also come up and foreign economic relationships will also improve, because now many states will be able to directly negotiate with India. So to deal with these new issues, that are going to crop up in the future, I think it is very important to have dialogues between the two countries. And as Dinesh Tripathi said, we should look towards ending this trust deficit through dialogues.

अखिलेश सुमन (राज्य सभा) : ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। एक बार मैं गया था जब केपी शर्मा ओली वहां प्रधानमंत्री थे। मैं वहां उनका इंटरव्यू लेने गया था। उस समय मधेश आंदोलन खत्म हो चुका था। लेकिन मैंने एक चक्कर काठमांडू से वीरगंज और फिर पोखरा होते हुए काठमांडू का लगाया और मैं उन सारे इलाकों में गया। इधर आंदोलन था इंडिया और नेपाल के बार्डर वाले इलाके में भी गया, नेपाल में मधेशी लोगों से भी मिला। जब तेल खत्म हो गया तो रक्शोल आकर तेल लेकर गया तो ये सारी स्थितियां मैंने देखी। मैंने केपी ओली साहब से कठिन सवाल भी किए, जो सारे समझे जाने वाले सवाल थे जो इंडिया के मांइड में थे जो नेपाल के लोगों के माइंड में नहीं इंडिया में ज्यादा थे। एक बार मुझे बार–बार ये लग रहा था कि हम तो माइक्रो इश्यूज पर बात करते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में कि दो सोवरियन स्टेट के बीच में किस तरह का रिश्ता होना चाहिए और हमारा और नेपाल के बीच में जो रोटी–बेटी का संबंध

है उसके बारे में लेकिन मैंने जो नेपाल के अंदर की स्थिति देखी और समझी वो काफी भयावह लग रही थी। क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट खुद डेवलप हुआ है नेपाल के अंदर जो तराई में रहने वाले लोग हैं और जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं उनकी एलीट के अंदर या जनता के अंदर अलगाव की भावना हो रही है। उस अलगाव की भावना को पाटना नेपाल और भारत सरकार दोनों को करना होगा। क्योंकि मधेश लोग अंततः नेपाल के हैं और हम नहीं कहना चाहेंगे कि वो हमारे इंडिया के हैं। मधेश लोग नेपाल के हैं, उनकी जिन्दगी नेपाल में है उनको नेपाल के लोगों के साथ मिलकर ही अपने भविष्य तलाशने होंगे और जो रिपरिजेन्टेशन के सवाल हैं वो हो सकता है एक बार संविधान बनने से नहीं बल्कि हो सकता है 25 बार संविधान संशोधन करने पड़े जो भारत में भी हुआ है। कई बार संविधान संशोधन हुए सिविलाइजेशन की प्रक्रिया चली, आरक्षण का प्रावधान किया गया आजादी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय से आरक्षण की बात हुई। इंदिरा गांधी ने भी आयोग बनाया था तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है जब कोई नेशन स्टेट अपने आपको आधुनिक लोकतंत्र में ढालता है तो मुझे ये महसूस हुआ कि नेपाल की सरकार को और नेपाल की जनता के अंदर भी जो मधेश और जो गैर मधेश हैं उनके बीच में बातचीत की प्रक्रिया बहुत ही गंभीर तरीके से शुरू होनी चाहिए या चलती रहनी चाहिए। क्योंकि जब में काठमांडू में कुछ लोगों से मिला तो उनके अंदर ये भावना थी कि हमें उस तरीके से नहीं देखा जाता है जैसे काठमांडू में पहाड़ के लोग अपने–आपको देखते हैं एक फीलिंग उनके अंदर है। और जब हम पहाड़ में गए जो पहाड़ बिल्कुल पहाड़ था जहां। वहां के लोगों ने कहा कि ये जो ब्लोकेड है ये मोदी ने करवाया है। एक महिला ने बाइट भी दिया कि मोदी ने करवाया है। लेकिन एक बात जो दिख रही थी कि टकराव कहीं नहीं हुआ। मधेश और पहाड़ के लोगों के बीच में काई फोर्स यूज नहीं हुई, जनता के बीच में कहीं लाठी नहीं चली, गोली नहीं चली। तो यह सिलवर लाइनिंग है और इस सिलवर लाइनिंग को बचाते हुए नेपाल के अंदर अगर इन दोनों समुदायों के बीच में शांति रहेगी तो शायद

इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी जिसको हम बार–बार कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी नेपाल को चलाना चाहती है या एजेंसी नेपाल को चलाना चाहती है उसको भी इनसाइटमेंट नहीं होगा। या यह नहीं होगा कि हमें ये करना है। राजनैतिक दलों की प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजनैतिक दल अपने हिसाब से जैसा इंडियन डेमोक्रेसी में होता है मैनेज करेंगे। लेकिन जो आंतरिक संवाद है नहीं तो श्रीलंका वाली स्थिति हमको लग रही थी उस समय भी और अभी भी वो परिस्थिति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है क्योंकि अगर भारत सरकार से भी उनका मोह भंग शुरू हो गया कि भारत सरकार ने हमको फोर्स किया। जब ये बोल रहे थे कि भारत सरकार ने फोर्स किया तो हम लोकल इलैक्शन में भाग ले रहे हैं तो अगर ये फीलिंग है तो एक समय भारत सरकार से ये आशा है कि वो हमें सहयोग करे। भारत सरकार पर यह तोहमत कि भारत सरकार ने ब्लोकेट करवाया और दूसरी बात यह निराशा कि भारत सरकार ने हमको फिर फोर्स कर दिया कि लोकल इलैक्शन में भाग लें। तो यह जो उनका भी एक सोवरेंट इंडीपेंडेंट डिसीजन है डेमोक्रेटिक स्पेस जो है तो उस स्पेस में अगर नेपाल की सरकार से भी मोह भंग हो और भारत की सरकार से भी मोह भंग हो तो ये बिल्कुल इल्म वाली स्थिति हो जाएगी और इस बात के प्रति नेपाल के लोगों को बहुत सचेत होना चाहिए।

जोगेन्द्र शर्मा (सीपीए के सेक्रेटिरिएट सदस्य) : मैं सुनने के लिए आया था। जमीनी हकीकत तो यही है नेपाल में भारत विरोधी भावना बढ़ी है और भारत में नेपाल विरोधी भावना बढ़ी है। कारण हम सब जानते हैं। और ये बात भी सही है जो अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने कही कि नेपाल के अंदर ये जो विभाजन हो रहा है; मधेशी और गैर मधेशी। गैर मधेशियों के बीच ये भावना है कि ये जो मधेशी आंदोलन है इसके पीछे भारत सरकार है। और जिस तरह का रिपरीजेंटेशन वो मांग रहे हैं अगर उस तरह का रिपरिजेंटेशन और उस तरह की तब्दीलियां कर दी गईं तो फिर ये मधेशी ही नेपाल पर राज करेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से ये भारत का राज नेपाल पर होगा ये भावना घर कर रही है। जनता के बीच में ये वहां की सच्चाई है। मैं जब भी जाता हूं

लोगों से बात होती है तो यही बात होती और इसका एहसास मधेशी लीडरों को भी है; ये बात नहीं है कि उनको एहसास नहीं है। लेकिन वहां पर जो विभाजन हो रहा है ये नेपाल से भी ज्यादा खतरनाक भारत के लिए होगा तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। चीन की चर्चा हुई, लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि सभी कंट्री तो सोवरेंट हैं। सभी को ये अधिकार हासिल है कि वो अपने व्यापारिक, सामरिक और हर तरह के हितों को न केवल सुरक्षित कर सके बल्कि उनका विस्तार भी कर सके। तो ये जो चीन की मौजूदगी की हकीकत है एक ये रिएलिटी है कि भारत में नेपाल विरोधी और नेपाल में भारत विरोधी भावना है एक ये जमीनी हकीकत है। और तीसरी हकीकत जिसकी चर्चा यहां पर नहीं हुई है वो मैं रखना चाहूंगा इस मौके पर 'जरूर' कि अगर उसपर गौर नहीं किया गया तो ये स्थिति आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा खराब होगी। वो ये है कि जिस तरह का अति राष्ट्रवाद आज भारत के अंदर पनप रहा है उसको बढ़ाया जा रहा है। हर चीज को उस चश्मे से देखा जा रहा है उसके चलते हुए चीन से ज्यादा हमारे अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध और जनता के रिश्तों पर उसका नकारात्मक असर पड़ेगा। अभी जो विजय ने रेफर किया था कि जो संविधान बना आखिर ये ब्लोकेट था क्या? मधेशी आंदोलन है क्या? मुझे याद है जब मैं नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन में गया था और वहां पर जब मैंने ब्लोकेट की चर्चा की और अपनी पार्टी की तरफ से उसको कंडम किया और ये कहा कि हम बिग बद्रर एटीटयूट में यकीन नहीं करते; नेपाल और भारत की जनता; हम एक–दूसरे को जुड़वा भाई मानते हैं। तो क्या प्रतिक्रिया वहां की जनता की रही और उसके बाद जितने भी लोगों से चर्चा हुई। तो ये जो आज अति राष्ट्रवाद की लहर हमारे देश में चलाई जा रही है जो हमारे देश की जनता को गुमराह कर रही है कि हर चीज को हम एक चश्मे से देखेंगे यदि हमारे हित में नेपाल की सरकार का या वहां का स्टैंड है तो वो हमारा दोस्त। और अगर वो हमारे हित में नहीं है या न्यूटरल है तो हमारा दुशमन। क्योंकि हमारे दुशमन को उससे फायदा मिलता है। ये जो अति राष्ट्रवाद है

ये आज जनता को भी उस तरह से अंधराष्ट्रवाद की तरफ लेकर जा रहा है जिसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। तो मैं ज्यादा बहुत ज्यादा सवाल हैं और बहुत सारी बातें कही गई हैं जिनसे मैं इत्तेफाक भी रखता हूं लेकिन ये जो चिंता है ये आज सबसे बड़ी है कि दोनों देशों के अंदर एक सेक्यूलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कॉन्सटीटयूशन उन्होंने अडोप्ट किया है और अब उसके तहत चुनाव होने वाले हैं। ये इलैक्शन भी एक टेस्ट होने वाले हैं कि इसमें भारत की क्या भूमिका रहती है; खासतौर से इस्टेबलिशमेंट की क्या भूमिका होती है। ये आने वाले दिनों के अंदर ये बातें बहुत सारी धाराओं की दिशा को तय करेंगी। अभी उन्होंने चुनावों के लिए 26 नवम्बर की तारीख तय की है यदि इतिहास को देखें तो भरोसा नहीं होता कि 26 नवम्बर को चुनाव हो जाएंगे लेकिन हम चाहेंगे कि वो समय पर हो जाए और दोहराया न जाए। ताकि वहां पर जन आकाक्षांए क्या हैं, कौन उनके प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, कौन नए स्टेक होल्डरस आते हैं और वहां की आंतरिक राजनीति एक उस डेमोक्रेटिक सेक्यूलर प्रकिया से कैस इवोवल होती है उसको देखा जाए उससे कुछ साकारात्मक चीजें जरूर निकलकर आएंगी लेकिन ये हो पाएगा कि नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि ये हो जाए और हमारा तो तमाम वहां की पार्टियों से और वहां की सरकार से हमारा यही निवेदन है कम से कम जो संविधान आपने अडोप्ट किया है कम से कम उसे इम्पलीमेंट तो कर दें; वो चुनाव तो करा दीजिए और अंतिम बात ये कि जो वहां पर हिन्दू राष्ट्र की जो एसेंस है वो तो संविधान में डलवा दी और वहां ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये बांह मरोड़ कर करवाया गया है और दिक्कत तो ये है कि विजय कहेंगे कि 'भाई तो तुम्हारे ही हैं'। प्रचंड साहब ने भी तो एक बार तो हां कर ही दी थी फिर बेक ट्रेक करना पड़ा और कहना पड़ा कि ये शब्द मत लाओ; तो ये तो किया ही है लेकिन इस तरह की दख्लंदाजी और ये जो होगा डेमोक्रेसी तो होगी लेकिन सेक्यूलर नहीं होगी तो उसके भी खतरे होंगे और यही खतरा सिर्फ नेपाल में ही नहीं हमारे भी हैं। और वो डेमोक्रेसी का एसेंस क्या रहेगा कारपोरेट

हाउसिस और कैबिनल फोर्सेस से हाई जैक रहेगी वो डेमोक्रेसी तो दोनों जगह कुछ सकारात्मक चीजें हैं जिन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ये जो दोनों तरफ नेगेटिव हैं दोनों तरफ तो यदि हम एक ऐसेंस में देंखें कि समस्याएं दोनों तरफ एक सी हैं उनको स्पेशल रिश्तों या रोटी–बेटी या कुछ जुमलों से या कुछ सहायता से इन चीजों से नहीं निपटाया जा सकता है। जो ग्राउंड रिएलिटी है उसके आधार पर कि ये हकीकत है और इसमें क्या करना चाहिए उसमें राजनैतिक पार्टियों को और जो तमाम तरह के संगठन हैं, जनआंदोलन हैं उनकी एक महत्ती भूमिका हम देखते हैं यदि वो अपनी महत्ती भूमिका अदा करेंगे तो तस्वीर ज्यादा बेहतर रहेगी। धन्यवाद।

अशोक कुमार सिंह : मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। मैं अहमदाबाद से आया हूं। मैं 2001 में वहां स्टडी करने गया था Human right of indigenous peoples in South Asian a comprehensive state response in India, Nepal and Bangladesh. तो मैं वहां के आदिवासी समाज से मिला था जो ज्यादातर पहाड़ी लोग थे। और पहाड़ के आदिवासी लोगों से ही मिला था। काठमांडू में मैं सारे आर्गेनाइजेशनस के लोगों से मिला था। कपिल श्रेष्ठा जी और नेपाल के एक्स प्रधानमंत्री थे लोकेन्द्र बहादुर चंद जी उनके साथ एक महीना मैं वहां पर रहा। तो मेरा अनुभव ये था जैसा कि अभी शर्मा जी ने कहा कि आज जो भारत हिन्दू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और वो आदिवासी समाज वहां पर हिन्दूइज्म के खिलाफ थे। उस समय भी जो माओवादी आंदोलन था वो हिन्दूइज्म के खिलाफ में था मतलब कि सेक्यूरिलिज्म के पक्ष में था। फिर यहां पर जो हिन्दूइज्म देख रहे हैं मतलब कि पूरे नेपाल का आदिवासी समाज है वो भारत के खिलाफ में हो गया जो पहाड़ी वर्सेस मधेशी का जो मामला है वो यही है कि जो मधेशी लोग हैं वो हिन्दूवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तो वहां के पहाड़ी आदिवासी लोग हैं वो डरे हुए हैं तो यही वजह है कि वहां के जो आदिवासी समाज और एक अवसर है यहां के कि यदि भारत के आदिवासी समाज और नेपाल का आदिवासी समाज चाहे तो ही ये रिश्ते मजबूत हो सकते हैं।

बाकी नेपाल के मधेशी और भारत के जनरल कम्युनिटी के लोग चाहेंगे कि ये भारत नेपाल का रिश्ता रिवाइव हो जाए ये संभव नहीं है। ये मेरा ओबर्जवेशन है। धन्यवाद।

सुबोध : सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़, जेएनयू में एमफिल का स्कॉलर हूं। प्रो. मुनि सर यहां मौजूद हैं तो मेरी तो औकात नहीं है कि मैं उनके सामने कुछ बोलूं। मैं कुछ अपनी कुछ बातें रखना चाहता था। मैं मूलतः बिहार के शिवान जिले का हूं, वो नेपाल और भारत की सीमा में पड़ता है। मेरी माँ मधेशी नेपाली है। तो मेरी कुछ चिंताएं हैं। मैंने आपकी जो मेल देखी थी उसमें ये था कि अभी जो नेपाल में बाढ़ से संबंधित परेशानियां हो रही हैं। उसके संबंध में भी कुछ बातें होनी चाहिए थीं लेकिन उसपर बहुत कम ही हुआ है। दूसरी जैसे कि नेपाल में पहाड़ी और मधेशी का मुद्दा अभी से ही नहीं बल्कि 1948 से ही ऐसा माहौल रहा है। पहले भाषा को लेकर था जब हिन्दी को रद्द किया गया था। उसके बाद 1970 और 1975 में भी बातें आगे बढ़ी और बाद में माओवादी आंदोलन जब शुरू हुआ तो उन्होंने इसको फेडलिज्म के नाम पर कि हम फेडलिस्टिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे और इस सब को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये मुद्दा तो नेपाल में हमेशा ही रहा है तो उसको लेकर यदि हम देखते हैं तो कहां तक लगता है जब हम पीपुल टू पीपुल रिलेशनस सुधारने की बात करते हैं, और जब हम ट्रैक टू लेवल डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो नेपाल का एक तबका जो पहाड़ी है उनका भारत के प्रति भिन्न दृष्टिकोण है। काठमांडू वैली में जो मीडिया बेस्ड है उनकी अलग सोच है। और जो मधेशी लोग हैं जो बॉर्डर के इलाके के लोग हैं वो अलग सोचते हैं। उसी तरह से दिल्ली, मुम्बई और चैन्नई में हैं नेपाली के बारे में उनकी समझ अलग होगी। लेकिन जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं जिनका मधेशी से बेटी–रोटी का रिश्ता है। क्योंकि ये बेटी–रोटी का रिश्ता पहाड़ी लोग और सीमा के इलाके के लोगों के साथ नहीं है बल्कि ये मधेशी के साथ है। तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम इसे कैसे हैंडल करते हैं। और दूसरी जो मेरी चिंता पहाड़ से है कि जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टस हैं या फिर जितनी भी नदी

परियोजनाओं पर काम हो रहा है। कोसी से शुरूआत हुई थी सबसे पहले तो उसके तीन उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि कनाल निकालकर सिंचाई हो क्योंकि उस इलाके में उपजाऊ मिट्टी है। दूसरा फ्लड कंट्रोल का और तीसरा हाइड्रो पावर का। लेकिन फ्लड कंट्रोल करने वाले काम में हम कहां चूक रहे हैं। क्या सूचना का सही से आदान–प्रदान नहीं हो पा रहा है, ये मुख्य कारण है या फिर ये कारण है कि जो प्रोजेक्टस तैयार किए गए थे उसमें इस चीज को ध्यान में नहीं रखा गया कि इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। जो नदी के किनारे वाले इलाके हैं उन लोगों की जमीन पर, उनकी खेती पर या उन पर इस चीज का क्या असर पड़ेगा क्या इस चीज को सही से नहीं आंका गया? कोसी परियोजना 1960 में शुरू हुई थी और सम्पन्न हुई थी 1965 के आज–पास और आज भी उस रीजन में बाढ़ की स्थिति वैसी ही है। अभी हाल ही में लाल बकिया और बागमती से नदी से संबंधित ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तैयार हुए हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इन सबको लेकर। और अभी हमारा इलाका भी बाढ़ में फंसा है। तो इसका क्या फ्यूचर है। अभी हम नदी परियोजना और हाइड्रो पावर प्रोजेक्टस की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी कल–परसों कुछ नेगोसिएशनस होने वाले हैं और कुछ मेमोरेंडम साइन भी होने वाले हैं। तो उसमें लोकल ऐसपरेशनस हैं उनको कितना ध्यान में रखा जाता है क्योंकि जो स्टेक होल्डरस होते हैं वो उस क्षेत्र से संबंधित नहीं होते हैं। यहां तक कि जब हम टेक टू डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो उसमें हम जिस बार्डर एरिया से संबंध रखते हैं उस इलाके से कितने लोग आते हैं। उनके कितने प्रतिनिधि आते हैं। और एक बात 1950 की जो फ्रेंडशिप एडं पीस की ट्रीटी है तो उस ट्रीटी के लिए (प्रो. लांबा भी उस समिति में होंगे, जिसमें उसको रिवाइव करने की बात चल रही है) उसमें उन लोगों का जो उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनका उसमें कितना प्रतिनिधित्व है। क्योंकि वो लोग ज्यादा महत्व रखते हैं उसमें फिर वो चाहे नेपाली तराई क्षेत्र से हों या फिर बिहार उत्तर प्रदेश के उन जिलों से हो जो कि उनकी सीमा से सटे हैं।

विजय प्रताप : आपने बहुत सवाल उठाए और उन सब पर आज की मीटिंग में चर्चा मुश्किल है और जैसे आपने कहा कि फ्लडस की बात ही नहीं हुई। फ्लडस के विषय में भी बात होनी चाहिए दोनों राष्ट्रों में जनता के एक हिस्से में ये गलतफहमी है जैसे नेपाली लोगों की इन्द्र भगवान से दोस्ती हो और वो षडयंत्र से बिहार यूपी में बाढ़ करवा देते हों, वैसे ही नेपाल के कुछ हिस्सों में है कि हमने सड़कें और बांध कुछ इस ढंग से बनाए हैं कि नेपाल फ्लड हो जाता है। और आपकी माँ क्योंकि नेपाली साइड से हैं तो आप उन परसेप्शनस को जरा ध्यान से देखिए और मधेश और बिहार–यूपी के रिश्ते के अलावा भी पहाड़ी जो हैं वो भी अपने को भारत से माइग्रेडिट मानते हैं और मधेशी तो कहते हैं कि हम तो यहीं के थे लेकिन पहाड़ी जो हैं कोई उदयपुर से गया है, कोई गुजरात से गया है ये सिर्फ शाह डायनेस्टी की बात नहीं है, जनता की भी बात है जिनको आज पहाड़ी नैसनलिज्म का प्रतीक माना जाता है उनके पुरखे भी सांस्कृतिक रूप से यहां से जुड़े रहे हैं और कभी न कभी उनके पुरखे जिनको आज हम हिन्दुस्तान कहते हैं उसमें रहे हैं। और ये जो भाषाई और रोटी–बेटी रिश्ते की बात है। पूरा पिथौरागढ़ और इधर बेतड़ी उनकी भाषा भी डोटई है। वो अपनी गढ़वाली से फर्क है और वो बार्डर एरिया की भाषा है। तो पहाड़ियों के बीच में भी यहां भी वैसा ही रिश्ता है जैसा मधेश का बिहार यूपी के बारे में है तो ये हमारा मीडिया भी मदेश के बारे में बात करेगा तो भारत वंशीय करेगा। नेपाल–इंडिया को रेशयली कोई फर्क नहीं है। हमारे यहां जो सब ग्रुपस हैं मंगोले तो वहां भी मोंगलाइटस हैं तो इस तरह से जो वननेस है लेकिन मेधेशी जो है वो यूपी बिहार से ही वननेस देखेगा और बाकी जो वननेस है उसको नहीं देखेगा तो वो एक समस्या है। अखिलेश जी ने जो कहा कि जो एक खाई बन रही है वो एक वास्तविकता है और उसको इसी तरह के संवादों से हम लोग पाट सकते हैं।

उद्धव : अभी बाढ़ के बारे में विजय प्रताप जी ने बता ही दिया। पूरा काठमांडू या उसके बाहर देखो फिर उसमें मीडिया देखो या पूरा पॉलिटीशियन। अभी नेपाल के

तराई हिस्से में बाढ़ का ज्यादा असर है। वो कहते हैं कि भारत ने सड़कें बना दीं उसी के कारण हमारे सीमा क्षेत्र में कहीं एक किलोमीटर में ऊंचा तो कहीं आधे किलोमीटर में सड़क नीचे बना दी है तो उससे ही नेपाल के वो इलाके डूब गए। मेरे ख्याल से परसों राष्ट्रपति ने एक मीटिंग की उस मीटिंग का मुद्दा भी यही था कि जब नेपाली प्रधानमंत्री भारत का दौरा करें तो उनको इस मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए। तो राष्ट्रपति का भी मुख्य एजेंडा यही था कि भारत की वजह से हमारे नेपाल में बाढ़ आई है। अब आप भारत की तरफ देखेंगे तो यहां पर तो बांध ही बांध है। हमारे नेपाल में कोसी बांध एकमात्र बांध है उसे भारत ने ही बनाया और नेपाल में बोला जाता है कि वो बांध भारत के हित में ही ज्यादा है। हमारे में और कोई बांध नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार को लगता है कि नेपाल में बांध ही बांध हैं और वो उन बांधों को खोल देता है कि जिससे भारत में बाढ़ आती है। जब मयावती मुख्यमंत्री थी तो वो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री को यह कहने आई थी कि वो नेपाल से बांधों को न खोलें क्योंकि उससे भारत के उन इलाकों में बाढ़ आ जाती है। तो जो है ही नहीं उसके बारे में भी चर्चा होती है। तो जैसे कि आपने बताया कि लोगों के साथ संवाद नहीं है, अभी नेपाल के लोगों को ये पता ही नहीं है कि नेपाल में बांध हैं कि नहीं हैं। और अभी जो नेपाल में बाढ़ की स्थिति है उसमें ये बात सही है कि वो कभी–कभार बांध के कारण भी हुई है। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि हमारा ही अतिक्रमण और हमारी ही सब चीजों से बाढ़ आ रही है लेकिन इसमें कोई सूचना भी नहीं है और जो है वो सही नहीं है। बस ये एक–दूसरे पर आरोप लगाने का ही काम चलता रहता है। और इसमें दोनों सरकारें भी अपनी–अपनी जिम्मेदारियों से हटकर एक दूसरे पर आरोप लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से बचने का आसान तरीका है। और रोटी–बेटी की बात है तो नेपाल में न केवल आम जनता बल्कि राजा घराने के लोगों ने भी भारत में शादियां की हैं। तो न केवल मधेश बल्कि

पूरे नेपाल में ऐसा होता है कि नेपाल के लोग भारत में शादी कर रहे हैं और भारत के लोग नेपाल में।

Prof. S. D Muni: I think everything has been discussed. But I think there are a couple of points that need to be discussed. India should stop blaming China for its poor relations with the other SAARC countries. The main cause of the problem with China is coming out of our own sense of insecurity and our incapacity to concoct a policy on how to deal with China. We have been unsuccessful in evolving that policy. We cannot match China economically, and in terms of aggressiveness or assertiveness. So instead of blaming the other SAARC countries, India should try to figure out the problem, because it is inherently Indian and only India can solve it. The problem has become worse, because irrespective of the likes or dislikes of the SAARC nations, the Chinese are coming into South Asia. They have their own strong and wise reasons, for their presence in South Asia. It is very difficult to cope with China in South Asia and if you are asking investments from China, why would the other SAARC nations not follow suit. They may also want to have a large trade with China like India. I agree that the other SAARC nations should take such decisions, by keeping into concern their own interests and not the fact that we should do this, so that we can be equal in India. In the 50s and 60s the SAARC nations(excluding India) were relating with the U.S and now on China. Any large power, which can provide a solace against a large neighbour, will definitely have the smaller countries falling back on their powers for technical reasons instead of substantive reasons. China factor would be there no matter what. Even if all the SAARC nations unite, even then it would be difficult for them to cope with China, and especially for India, because it is the main country that is being affected by China and is not capable of dealing with the problem. Therefore all the SAARC nations, especially Nepal should be cautious in its own way, on whether it wants to have a dependency relation with China and wants to give it a major scope or not. These are legitimate questions that need to be asked. Uddhab wrote an article on these issues, which let the Neaplese brood over them. India's major concern is China in South Asia and India has to deal with if on its own. It cannot fix it with any neighbour. If India is concerned about any neighbour then it should not alienate the neighbour, because 50-60% of their response to China would depend on their alienation. Indian gets blackmailed because it alienates its neighbours. It should not get blackmailed and for that it should stop alienating its neighbours. If it stops alienating its neighbours, then there is no

question of question of them blackmailing India. China is a major challenge, but India should not get fixated because of this. China is coming to South Asia, because it wants South Asian markets, it is worried about Tibet, it is wants to expand into Indian Ocean, it is worried about the western influence on this part of the world. It is not Nepal who is letting China in. If Nepal had tried to stop them from letting in, they would have overthrown Nepal long ago. No SAARC country is capable of stopping their entry into this part of the world. So the first point I wanted to make was, that China is a major threat to India's foreign policy and India should gear up to dealing with it that to put the blame on the other SAARC countries.

Nepalese nationalism against India is another point that came up. Maybe the Indian nationalism is not anti-Nepal, but in the global context the Indian nationalism has become distorted. Nationalism is on the rise, because the right is on the rise. This is true for every country. Nationalism is getting distorted by having the sectarian levels like religion, caste, status and ethnicity. Both India and Nepal are guilty of this. Why should I rise from my seat when my national anthem is playing, why should my university build a tank to make my students and colleagues more nationalists, why should a person belonging to a minority sector be imprisoned or asked to go to another country if he speaks against the government? I don't see the logic behind all this. Nobody can see the logic behind all this because there is no logic. It is completely illogical. So it is us, who have distorted our nationalism. Pakistanis have also done this. They ethinicized their nationalism and we religionised ours. All this *roti-beti* and *Tarai* is nonsense. All the neighbours around India were related to India culturally or civilization ally, but not politically. Then how are the people residing in hills different from the Indians? This distinction has been made by the Nepali leaders and they are using their nationalism against India to beat *Tarai*. They wanted to consolidate an ethnic context of nationalism they told the people, who are dependent of *Tarai* that, India was supporting *Tarai*. This will tear Nepal apart and India will also end up in the same jam if it doesn't stop its secretarial nationalism. This is not only true for India but for any country. This is because all countries are diverse, multicultural, multi ethnic and multi religious. If we emphasize any single component, then we would be alienating rest of the communities and fragmenting our country, to the level of instability and insecurity. This is not a good option for Nepal nor for India. So we should look to stop having this band of nationalism and getting in to it and correct it by ending its distortion.

Does anyone remember how Nepal has behaved in the last few decades? What about the anti-Rana revolution, what about the Gorkahs and Dalwas accusing India of interference, people who were unfavorable to King Tribhuvan calling India a dominator, I think Mahindra's first attack after taking over was on Indian military mission. All this was coming out in Nepal, primarily for preserving the regime, to remain powerful and to sustain it. It is the internal power struggle that distorts nationalism, be it ethnic, anti-national or any other form of struggle. Nepal's relations with India are basically driven by the fact whether they will be in power or not. This is political business. And as others stated earlier, security has driven India away from Nepal. The security issue has led us to micromanagement. I remember Nehru writing letters to the P.M of Nepal, Matrika Prasad Koirala, in which he asked him why he spent enormous amounts of money, on Nepal's commonwealth delegation in London. What has that got to do with security or India's interest in Nepal? This is India's mindset about Nepal. Indian ambassador C.P.N Singh changed governments every now and then for preserving the regime. Everyone wants to do micromanagement and preserve the regime. We are being driven into micromanagement by security and Nepal by regime concerns. This will not do because both the countries have changed a lot. Since 2005-2206 the degree of exposure and awareness that has gone into Nepal in nobody's business. None of us have been able to follow it properly. It has come out of people's revolution. The Maoist movement was primarily responsible for it. Young ambitious people, enterprising and dynamics, who are aware of the situation and know that business as usual, will not do. So what are the changes that have to be brought about? The main change is development. It has to be put over everything else as the first priority. Is it the national priority of Nepal? If yes then only it has a constructive India or China policy. SAARRC countries were trying to relate with China to use it as a transit point. You bring petro to Kathmandu via China. This is just a way to make money in the name of development. If development had been the first priority one would not sabotage money. When Bhattrai signed the BIPA agreement and took it back to Kathmandu, his own party raised objections against it. If development is not Nepal's first priority, then their Indian policy will not change no matter what. They have to change their policy. They can't even relate with China. India too has to build in development as a part of its security approach. Currently Nepal's development is not India's priority yet. Modi's speech in the parliament of Nepal has no basis. It is completely illogical. When development becomes one of India's priorities, then the first question which will arise is going to be people to people

relations. Meeting people's aspirations is what people to people relation is. For that one has to allow and encourage investments, have an infrastructure, connectivity and facilitate power and tourism. How have we facilitated Nepal in the last 20 years? Not even equal to what India has done in Afghanistan. Not even equal to the extent it is doing in Bangladesh. If this is the situation, then one should not expect anybody from Nepal to come and settle in India or think of India as a great country. If Nepal and India preserve their nationalism and security respectively, it would be good. But their relations will only improve if they keep development as on both these emotions as an important priority. The China factor would still loom, but that has to be dealt with separately and by India alone, not be any other country or its help to India.

Rahul Barua: Thank you all for being part of the conference and especially to all the speakers for identifying issues that are so pertinent in an India-Nepal relation today. I would just like to conclude by saying, that we have been always blaming various Indian agencies for messing up things with our neighbours especially with Nepal It is the intelligence agencies that have mishandled the situation and their inputs seem to be misleading. The political leaders, in both the countries have also played against each other and are the main cause of the poor and deteriorating Indo-Nepal relations. The china phobia has become a major issue and India has made it a phobia as a part of its aggressive nationalism posture recently.

As far as India's development support to Nepal is concerned, it has been a knee-jerk reaction in recent past. An example to this is When China had recently submitted a full fledged DPR and feasibility report on railway link from China to Nepal linking Kathmandu and further Kathmandu and Pokhra rail link, then India all off a sudden announced rail link between Kathmandu and Delhi which should have been implemented a decade ago. This made Nepalese noticing India's counter response to Chinese aggressive postures in the region. We can't even run our bus services between India and Nepal effectively with travellers having to spend considerable discomfort time at the borders, India has been extremely slow in implementing various projects in Nepal, the proposed postal road that India is supposed to construct more than two decades ago are yet to see its light, then how can we build railway links in challenging circumstances where there are various obstacles in Nepal?

There is an impression in Nepal where it is perceived that India is not serious and interested in development in Nepal and it is just trying to compete with China, more so politically rather than economically. This perception needs to be reversed to improve public perception in Nepal.

More people to people contacts are to be built between these two immediate neighbours and onus of responsibilities lie with India to further its socio-cultural-economic bonding.

SADED's efforts are commendable and most appropriate at a time when India and Nepal are going through most challenging circumstances.